एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

349. [*Transferred to the 4th August, 1988*]

मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पीने के पानी की पूर्ति

350. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में दूर दराज के एक ही गांव के उप-ग्रामों में जैसे तोला, माजरा, द्वारा इत्यादि, छोटे-छोटे समूहों में रह रहे आदिवासी व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक को एक इकाई मान कर उन्हें कम से कम एक स्वस्थय पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों के ऐसे उप-ग्रामों की संख्या कितनी है जिनका पता लगा लिया गया है और उन में से ऐसे उपग्रामों की संख्या कितनी है जहां कम से कम एक स्वस्थ पेयजल स्रोत उपलब्ध करा दिया गया है ;

(ग) बाकी बचे उपग्रामों में पेयजल के कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था कब तक कर दिए जाने की संभावना है , और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नहीं है, तो सरकार ऐसा करना आवश्यक क्यों नहीं समझती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देशिकाओं में एक समस्याग्रस्त गांव (राजस्व गांव) में प्रत्येक 250–300 लोगों की जनसंख्या के लिए एक स्रोत (हेण्ड पम्प अथवा स्टैण्ड पोस्ट ट्यूबवैल सहित) के लिए व्यवस्था है । तोला, माजरा, पारा आदि जैसे उपगांवों में छोटे-छोटे समूहों में रह रहे आदिवासियों जो राजस्व गांव का अंग हैं, को भी प्रत्येक 250–300 लोगों के लिए एक स्रोत के उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं । पम्पों की संख्या और इसके स्थान के बारे में निर्णय करते समय, ऐसी छोटी बसावटों सहित गांव की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) स्वच्छ पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था की निगरानी केवल चयन किए गए समस्याग्रस्त गांवों के लिए ही की जा रही है । आदिवासी गांवों के उप-गांवों के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर पर अलग से कोई निगरानी नहीं की जा रही है, क्योंकि वे राजस्व गांवों के अंग हैं ।

(ग) उप-गांवों जोकि राजस्व गांवों के अंग हैं, सहित शेष सभी समस्याग्रस्त गांवों को सातवीं योजना के अंत तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of AIR/TV Centres at Patiala

351. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have considered the desirability of establishing Radio Stations/T.V. Centres at the headquarters of Zonal Cultural Centres in the country; and

(b) if so, by when Patiala in Punjab would be provided with these facilities?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Yes, Sir. This is one of the aspects kept in view